International Journal of Financial Management and Economics

P-ISSN: 2617-9210
E-ISSN: 2617-9229
IJFME 2024; 7(2): 234-236
www.theeconomicsjournal.com
Received: 25-07-2024
Accepted: 02-10-2024

पूजा कुमारी
शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

Corresponding Author:
पूजा कुमारी
शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

प्राथमिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान का छात्र पर प्रभाव

पूजा कुमारी

DOI: https://dx.doi.org/10.33545/26179210.2024.v7.i2.367

सारांश
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत सरकार की अग्रणी पहले में से एक है, जो भारतीय सविधान द्वारा निर्दिष्ट समय–बद्ध–केंद्रित तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (जिसे यूईई भी कहा जाता है) को पुरा करने के लिए है। सविधान में 86वें सशोधन के साथ भारत में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार बन गया। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के युवा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के हकदार हैं। एसएसए पहल का नेतृत्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा किया जाता है। वर्ष 2000 से 2001 तक एसएसए पहल प्रभावी रही। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू होने के साथ ही एसएसए पहल में संशोधन किए गए। एसएसए योजना को परू देश में राज्य और स्थानीय सरकारों के सहयोग से सचांलित किया जाता है, ताकि 1.2 मिलियन घरों में 193 मिलियन बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को वर्ष 2018 में समग्र शिक्षा अभियान पहल में मिला दिया गया। 21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था एसे वातावरण में उन्नति कर सकती है जो रचनात्मकता एवं काल्पनिकता, विवचे नात्मक सोच और समस्या के समाधान से संबधित कौशल पर आधारित हो। अनुभवमूलक विश्लेषण शिक्षा और आर्थिक उन्नति के मध्य सुद्रढ सकारात्मक सबंध होते हैं। भारत में स्कूल जाने वालों की आयु 6–18 वर्ष के मध्य की 30.5 करोड़ की (2011 की जनगणना के अनुसार) की विशाल जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का 25ः से अधिक है। यदि बच्चों को वास्तविक दुनिया का आत्मविश्वास से सामना करने की शिक्षा दी जाए तो भारत में इस जनसांख्यिकीय हिस्से की सपंर्ण सामर्थ्य का अपने लिये उपयोग करने की क्षमता है। सधारणीय विकास लक्ष्य 2030 को अंगीकार करने के बाद ध्यान माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक 'गुणवत्ता के साथ निष्पक्षता' पर स्थानांतरित हो गया है।

कूटशब्द : समय–बद्ध–केद्रित तरीके, सार्वभौमिकरण, समग्र शिक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विवचे नात्मक सोच, अनुभवमूलक विश्लेषण, सपंर्ण सामर्थ्य, एवं गुणवत्ता के साथ निष्पक्षता

प्रस्तावना
सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का आरंभ प्राथमिक शिक्षा सन् 2001 में हुआ है। ये कार्यक्रम जब अटल बिहारी बाजपयी प्रधानमंत्री थे। तभी चलाया गया था। इसका उद्धश्ेय सभी को शिक्षा से है। 'सब पढ़े सब बढ़े' इसका नारा था। सर्व शिक्षा अभियान का छात्रों पर गहरा प्रभाव पडा है। इसके कारण छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है। छात्रों का छीजन दर घटी है। इसके अंतर्गत छात्रों को पाठ्यपुस्तक, पोषाक, छात्रवृति, इत्यादि सुविधायें दी जाती है। इसके अंतर्गत माध्याह्न भोजन योजना (Mid day meal yojna) को चलाया गया है एवं आयरन फोलिक एसिड एवं क्रीमी की दवाई भी विद्यालय में भेजी जाती है ताकि छात्र स्वस्थ रहें सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहीं है। सर्व शिक्षा अभियान विद्यालयों में शिक्षकों की पुर्ति कर रही है एवं शिक्षकों को वेन भी दे रहीं है। विद्यालय में डेक्स बंचे एवं विद्यालय भवन के लिए भी सर्व शिक्षा अभियानद्ध पैसा देती है। सर्व शिक्षा अभियान विद्यालय के रखरखाव का भी ध्यान रखती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई छोटे–छोटे कार्यक्रम चलाये गये है। जो छात्रों के हित में है। हाल में हो रही शिक्षक भर्ती इस अभियान की एक कड़ी है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा पर बहुत खर्च कर रही है। जिससे छात्रों की उपस्थिति विद्यालय में बढ़ी है एवं छात्रों पर इसका साकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत सरकार की अग्रणी पहलों में से एक है, जो भारतीय सविधान द्वारा निर्दिष्ट समय–बद्ध–केंद्रित तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (जिसे यूईई भी कहा जाता है) को परू करने के लिए है। सविधान में 86वें सशोधन के साथ भारत में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार बन गया। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के युवा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के हकदार हैं।

एसएसए पहल का नेतृत्व मानव ससं ाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा किया जाता है। वर्ष 2000 से 2001 तक एसएसए पहल प्रभावी रही। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू होने के साथ ही एसएसए पहल में संशोधन किए गए। एसएसए योजना को पूरे देश में राज्य और स्थानीय सरकारों के सहयोग से सचांलित किया जाता है, ताकि 1.2 मिलियन घरों में 193 मिलियन बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को वर्ष 2018 में समग्र शिक्षा अभियान पहल में मिला दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के घटक एसएसए पहल की विशेषताएं निम्नलिखित हैंः

1. यह रणनीति एक निश्चित समय सीमा के भीतर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को लागू करने के लिए स्थापित की गई थी।
2. यह कार्यक्रम देश के सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है।
3. यह बच्चों को सहायता प्रदान करके और उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके सामाजिक निष्पक्षता को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
4. प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में स्कूल प्रबंधन बोर्ड, पंचायती राज सगं ठन, स्थानीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, अभिभावक शिक्षक संगठन, माता शिक्षक संगठन और जनजातीय स्वायत्त प्राधिकरणों को सुविधा प्रदान की जाती है।
5. यह राज्यों, सघीय सरकार और स्थानीय प्राधिकरण के बीच शैक्षिक सहयोग स्थापित करता है।
6. यह राज्यों को प्राथमिक शिक्षा के बारे में अपना द्रष्टिकोण बनाने की स्वतंत्रता देता है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लक्ष्य
7. पाठ्यक्रम, शैक्षिक डिजाइन, प्राथमिक शिक्षा और प्रशासन सभी। कार्यक्रम के लक्ष्य हैं। कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं।
8. उन क्षेत्रों में नये संस्थानों का निर्माण करना जहां कोई मौजूदा शैक्षणिक सुविधाएं नहीं हैं। वैकल्पिक शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना।
9. पीने के लिए पानी, अधिक कक्षाएं और शौचालय बनाकर वर्तमान स्कूल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
10. सेवा और स्कूल संवर्द्धन निधि के प्रशासन की देखरेख करना ।
11. छात्रों को निःशुल्क वस्त्र एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।
12. जिन संस्थानों में शिक्षकों की कमी है, वहां अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षण बल को और अधिक मजबतू करना।
13. विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ जीवन कौशल प्रदान करना।
14. महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाना।
15. अतिरिक्त आवश्यकताओं वाले या विशेष रूप से सक्षम युवाओं को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना ।
16. अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति परिवारों भूमिहीन खेत मजदूरों, इस्लामी अल्पसंख्यकों और अन्य लोगों के बच्चों के लिए उचित शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देना ।
17. पारपंरिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की बहे तर समझ प्राप्त करना।
18. स्कूलों में युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करके डिजिटल अंतर को कम करना।
19. कठोर प्रशिक्षण, शिक्षक–शिक्षण सामग्री के उत्पादन के लिए वित्त पोषण, तथा ब्लॉक, क्लस्टर और जिला स्तर पर अधिक मजबूत शैक्षणिक सहायता प्रणाली के माध्यम से वर्तमान स्कूल शिक्षकों की क्षमता और योग्यता में सुधार और संवर्धन करना।
20. सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत पहल 2014 में।

योजना ने 'पढ़े भारत बढ़े भारत' अभियान शुरू किया। पढे भारत बढ़े भारत परियोजना का उद्देश्े य कक्षा 1 और 2 में बच्चों के पढ़ने, लिखने और गणित कौशल को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य युवाओं को व्यावहारिक द्रष्टिकोण से पढ़ने की समझ और लिखने के लाभों का एहसास कराने में मदद करना है। पढ़े भारत बढे भारत पहल बच्चों के पढ़ने के महत्व पर जोर देती है ताकि वे बेहतरीन लेखक और पाठक विकसित कर सकें। यह पहल इस बात की गारंटी देती है कि भारतीय भारतीय स्कूल उच्चगुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की अपनी क्षमता में सुधार करें इस पहल को दो–तरफा रणनीति में डिजाइन किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैः

1. बच्चों को समझ के साथ लिखने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करके उनके सज्ञांनात्मक विकास को बढ़ाएं, साथ ही।
2. बौद्धिक और सांस्तिक क्षेत्र से जुड़ी गणित में सकारात्मक और स्वाभाविक रुचि को बढ़ावा देना ।

सर्व शिक्षा अभियानद्ध एक एकीत प्राथमिक शिक्षा पहल है। इस पहल का उद्देश्य सभी छात्रों को एक पवू र्निधारित क्रम में समुदाय–स्वामित्व वाली गुणवत्तापर्ण शिक्षा प्रदान करके अपनी मानवीय क्षमता में सुधार करने का अवसर देना भी है। यह उच्च–गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा की व्यापक आवश्यकता की प्रतिक्रिया है। महबबू ने सर्व शिक्षा अभियानैद्ध पहल की वकालत करने के लिए 'स्कूल चलें हम' कविता लिखी। इस अभियान में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के हिसाब से तय है। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शैक्षिक सत्र 2022–23 में 9,184 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी मिली थी। इस राशि में से सबसे ज्यादा 3,424 करोड. रुपये शिक्षकों के वेतन के लिए थे। इसके अलावा, गुणवत्ता शिक्षा के लिए 1,938 करोड़ रुपये, माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब के लिए 1,565 करोड. रुपये और राज्य के मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए 889 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया गया था। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के तहत चल रहे कार्यक्रमों में दिक्कतें आ रही हैं। इनमें से एक वजह यह भी बताई गई है कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही है।

एक अध्ययन के मुताबिक, सर्व शिक्षा अभियान ने बुनियादी सुविधाओं पर सकारात्मक असर डाला है, लेकिन इससे प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पाया है।

21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था एसे वातावरण में उन्नति कर सकती है जो रचनात्मकता एवं काल्पनिकता, विवचे नात्मक सोच और समस्या के समाधान से सबंधित कौशल पर आधारित हो। अनुभवमूलक विश्लेषण शिक्षा और आर्थिक उन्नति के मध्य सुद्रढ सकारात्मक सबधं होते हैं। भारत में स्कूल जाने वालों की आयु 6–18 वर्ष के मध्य की 305 करोड़ की (2011 की जनगणना के अनुसार) की विशाल जनसख्ंया है, जो कुल जनसंख्या का 25ः से अधिक है। यदि बच्चों को वास्तविक दुनिया का आत्मविश्वास से सामना करने की शिक्षा दी जाए तो भारत में इस जनसांख्यिकीय हिस्से की सपूंर्ण सामर्थ्य का अपने लिये उपयोग करने की क्षमता है। सधारणीय विकास लक्ष्य 2030 को अंगीकार करने के बाद ध्यान माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक 'गुणवत्ता के साथ निष्पक्षता' पर स्थानांतरित हो गया है। कुछ महीनों पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक उद्बोधन (मन की बात) में गुणवत्ता के महत्व पर इन शब्दों में जोर दिया थाः 'अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था किंतु अब वक्त आ गया है कि ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। अब सरकार को स्कूलिंग की बजाय ज्ञान पर अधिक ध्यान

देना चाहिए।' मानव ससांधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने भी घोषणा की थी कि 'देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होगा।' स्कूलिंग की बजाय ज्ञानार्जन पर ध्यान स्थानांतरित करने का अर्थ इनपुट से नतीजों पर ध्यान देना है।

निष्कर्ष

राज्य सरकारों की साझदे ारी के साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) ने आरम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में यथेष्ट सफलता पाई है। आज देश के 14.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों में 19.67 करोड़ बच्चे दाखिल हैं। स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ कर जाने की दर में यथेष्ट कमी आई है, किंतु यह अब भी प्राथमिक स्तर पर 16ः एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 32ः बनी हुई है, जिसमें उल्लेखनीय कमी करना आवश्यक है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विद्यालयों से बाहर बच्चों की संख्या वर्ष 2005 में 135 लाख से घटकर वर्ष 2014 में 61 लाख हो गई, अंतिम बच्चे की भी विद्यालय में वापसी सुनिश्चित करने हेतु संपर्ण प्रयास किये जाने चाहिए। जैसा कि स्पष्ट है कि भारत ने स्कूलिंग में निष्पक्षता एवं अभिगम्यता सुनिश्चित करने के गले में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि एक औसत छात्र में ज्ञान का स्तर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) की पांचवी कक्षा के छात्रों की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ पाने की समझ से जुड़े प्रश्नों के आधे से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दे पाने वाले छात्रों का प्रतिशत केवल 36ः था एवं इस सबंध में गणित एवं पर्यावरण अध्ययन का आंकड़ा क्रमशः 37ः एवं 46ः है।

विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिये केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें नवीन व्यापक द्रष्टिकोणों एवं रणनीतियों को बना रहे हैं। कुछ विशेष कार्यक्षेत्रों की बात करें तो अध्यापकों कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली कार्यविधियों छात्रों में ज्ञान के मूल्यांकन एवं निर्धारण, विद्यालयी अवसंरचना, विद्यालयी प्रभावशीलता एवं सामाजिक सहभागिता से संबधित मुद्दों पर कार्य किया जाना है।

ऐतिहासिक रूप से बिहार शिक्षा और अध्ययन का एक प्रमुख केद्रं रहा है। हालांकि, हाल के वर्षो में, सभांवित जनसंख्या विस्फोट और खराब शासन के कारण, राज्य में शिक्षा की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसका एक लक्षण सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) पर बिहार का कम व्यय है – प्राथमिक शिक्षा के लिए केंद्र की प्रमुख योजना और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राज्य राज्य द्वारा 2012–13 में कार्यक्रम पर 5,229 करोड़ रुपये खर्च किए, जो 2013–14 में घटकर 4,613 करोड़ रुपये हो गया और 2014–15 में बढ़कर 5,913 करोड़ रुपये हो गया कार्यक्रम के लिए स्वीत कुल निधियों के अनुपात के रूप में ये आंकड़े क्रमशः 51ः, 68ः और 76ः थे (स्रोत–एसएसए पोर्टल)। विदित हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रेल 2010 में लागु हुआ। यह कानून सविधान के अनुसार 45 ए में है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कई बातें रखी गई है जैसे

- 6–14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो।
- हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक मध्य विद्यालय हो।
- छात्र शिक्षक अनुपात 30ः1 हो।

इस प्रकार हम कह सकते है कि प्राथमिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान का छात्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

सदंर्भ ग्रंथ

1. सरोज यादव (2001), ष्प्राइमरी शिक्षक" पृष्ठ संख्या – 121
2. उमेश चंद्र अग्रवाल (2004), भारतीय आधुनिक शिक्षा जननी – सर्व शिक्षा अभियान, वृहद् लक्ष्य– कमजोर प्रयास पृष्ठ – 9–131
3. डॉ के. के तिवारी (1998), "भारतीय शिक्षा–विकास और समस्यायें" साहित्य प्रकाशन, आगरा, पृष्ठ–36, 44, 58–781
4. मृदुल कुमार वर्मा एव ं शरत वर्मा (1999), "भारतीय आधुनिक शिक्षा बाल श्रमिक कल्याण केन्द्रों में शिक्षको ं की समस्यायें" पृष्ट–51।
5. महेश भार्गव (1992), "आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण व मापन" एच. पी. भर्गव बुक हाउस, आगरा, बारहवाँ सस्ं करण, पृष्ठ संख्या – 263–265, 2681
6. एच. के. कपिल (1992–93), "अनुसंधान विधियाँ, भार्गव बुक हाउस, आगरा, पृष्ठ सख्ं या 10–11
7. रामशकल पाण्डेय (2003), "उदीयमान भारतीय समाज मे ं शिक्षक विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृष्ठ संख्या – 10–111
8. रामशकल पाण्डेय, "भारतीय शिक्षा की ज्वलंत समस्याये,ं वोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्टीब्यूटर्स, इलाहाबाद, पृष्ठ सख्ं या – 35–36, 51–531
9. आर.ए. शर्मा (1998), "शिक्षा अनुसंधान" सर्यू ा पिब्लकेशन्स, मेरठ, पृष्ठ–48–49ए 63–641
10. आर. ए. सक्सेना स्वरूप (1998), "शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत" सयू ा पब्लिकेशन, मेरठ, पृष्ठ–12–141
11. रामशकल पाण्डेय, "भारतीय शिक्षा की ज्वलंत समस्याये,ं वोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्टीब्यूटर्स, इलाहाबाद, पृष्ठ सख्या – 35–36, 51–531
12. पी. डी. पाठक (1992), "भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृष्ठ संख्या – 15, 3131
13. पाठक एवं त्यागी (1995), "शिक्षा के सामान्य सिद्धांत", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृष्ठ–1691
14. मीना बुद्धि सागर राठौर, "भारतीय आधुनिक शिक्षा" अप्रैल – वर्मा मधुलिका (2001), "शाला अनुभव शिक्षण प्रशिक्षण का आवश्यक पहलु" पृष्ठ–36–471